श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदया, अभी क्वेश्चन बहुत हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपने स्वयं कहा कि यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।

श्री सभापति: वह सही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसलिए मैं यह बतला दूं कि इसमें सरकार क्लैनलीनेस का कोई मॉडल बाहर नहीं रख सकती। आप पूरे का पूरा बाहर शहर साफ करके रख दीजिए लेकिन अंदर के घर के फूलदान में पानी सात दिन पड़ा है तो यह उसमें पैदा होता है। इसीलिए इसमें हमने आपसे कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका बाहर की साजो-सफाई से कोई लेना-देना नहीं है, इसका कोई वेक्सीन नहीं है, इसके बाद की कोई ऐसी दवा नहीं है केवल सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसलिए इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें एक ही काम कर सकती हैं कि यह जानकारी लोगों को दें कि अपने घर के अंदर साफ पानी को भी बदल-बदल कर भरें, क्योंकि यह अकेला मच्छर है जो साफ पानी में पैदा होता है, जो गंदगी में नहीं पैदा नहीं होता है।

श्री प्रेम गुप्ता: सर,....

श्री सभापति: अब हो गया, छोड़िए।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, on the lighter side मदल लाल खुराना जी और जार्ज फर्नांडीज जी नालियां क्यों साफ कर रहे थे दिल्ली में। बोल रहे थे कि डेंगू खा गया। जार्ज फर्नांडीज जी वहां जाकर के गंदगी उठा रहे हैं। ..(**व्यवधान**)..

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: سرکار نے کیا سوچا ہے، سرکار کیا کرے گی؟

_____مداخلت_____

†**मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी:** सरकार ने क्या सोचा है, सरकार क्या करेगी? ..(**व्यवधान**)..

Child sex-ratio

*89. SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN:†
SHRI R.P. GOENKA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent joint report by the Registrar of Census, UNFPA and her Ministry, entitled 'Missing-Mapping the Adverse Child Sex Ratio in India' has shown an alarming downward trend in the Child sex-ratio, in the last decade;

†Transliteration of Urdu speech.

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prithviraj Chavan.

(b) whether the prosperous States like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Gujarat have revealed the worst performance with as low a ratio as 800 girls for every 1000 boys born;

(c) the exact figures of child sex-ratio for all the States; and

(d) the steps, if any, taken by Government to correct the situation?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) As per Census figures, the child sex ratio at national level has declined from 945 girls per 1000 boys in 1991, to 927 girls per 1000 boys in 2001. The situation is worse in many States like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Gujarat which have a child sex ratio of 793, 820, 897 and 878 respectively. There are 16 districts in the country having less than 800 girls per 1000 boys; out of which 10 are in Punjab, 5 in Haryana and 1 in Gujarat.

(c) State-wise figures of child sex ratio in the age group 0-6 years in Census 2001, as compared to the figures of Census 1991 are given in the statement-I (*See* below).

(d) The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, was enacted by the Parliament with a view to prohibit sex selection before or after conception, for regulating the use of pre-natal diagnostic techniques, for prevention of their misuse for sex determination leading to female foeticide, and for matters connected therewith or incidental thereto. The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002, has brought the technique of pre-conception sex selection and use of ultra sound machines within the ambit of this Act, and has made punishments prescribed under the Act more stringent. It also empowers the Appropriate Authorities for search, seizure and sealing of machines, equipments and records.

As per the reports received from States/UTs, more than 21,600 centres conducting pre-natal diagnostic procedures, including ultrasonography, have been registered. 418 complaints have been filed in the Courts/with the police for various violations of the Act/Rules.

It is, nevertheless, recognized that mere legislation is not enough to deal with a problem that has roots in social behaviour and prejudices. Some of the reasons commonly put forward to explain the consistently low sex ratio are son preference, neglect of the girl child resulting in higher mortality at younger age, female foeticide and infanticide, and male bias in enumeration of population. Various activities have been undertaken to create awareness against the practice of pre-natal determination of sex, and female foeticide, through Radio, Television and print media units. Workshops/seminars have been organized through Voluntary Organizations at State/regional/district/block levels to create awareness against this social evil. Cooperation has also been sought from religious leaders, as well as the medical fraternity, to curb this practice.

Recently, the Department of Family Welfare has launched a new initiative 'Save the Girl Child Campaign' with a view to lessen son preference by highlighting achievements of young girls. The teenage tennis champion, Ms. Sanya Mirza, has been appointed as the first Ambassador for this campaign. This theme has been adopted for the Department's tableau for the next Republic Day Parade also.

Statement-I

Child Sex Ratio in the age group of 0-6 years

Sl. No.	States/UTs	1991	2001
1	2	3	4
1.	Punjab	875	793
2.	Haryana	879	820
3.	Chandigarh	899	845
4.	Himachal Pradesh	951	897
5.	Jammu & Kashmir	N.A.	937
6.	Delhi	915	865
7.	Rajasthan	916	909
8.	U.P.	927	916

1	2	3	4
9.	Bihar	953	938
10.	Orissa	967	950
11.	Madhya Pradesh	941	929
12.	Uttaranchal	948	906
13.	Jharkhand	979	966
14.	Chhattisgarh	984	975
15.	Sikkim	965	986
16.	Arunachal Pradesh	982	961
17.	Nagaland	993	975
18.	Manipur	974	961
19.	Mizoram	969	971
20.	Tripura	967	975
21.	Meghalaya	986	975
22.	Assam	975	964
23.	West Bengal	967	963
24.	Gujarat	928	878
25.	Daman & Diu	958	925
26.	Dadra & Nagar Haveli	1013	973
27.	Maharashtra	946	917
28.	Andhra Pradesh	975	964
29.	Karnataka	960	949
30.	Goa	964	933
31.	Lakshadweep	941	974
32.	Kerala	958	963
33.	Tamil Nadu	948	939
34.	Pondicherry	963	958
35.	A & N Islands	973	965

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the figures given by the Minister as indicated in the Census Report and also in the report which I have mentioned, a Joint Report by UNFPA and Registrar of Census, show an alarming decline in the child sex ratio in the last decade—from 945 girls per thousand boys, it has come down to 927 girls per thousand boys. The States of Punjab, Harayana, Himachal Pradesh and Gujarat are the worst affected. Sir, the Pre-natal Diagnostic Techniques Prevention Act has been amended, but if you look at the figures given by the Minister, out of 21,000 or so registered centres, I do not know how many unregistered centres there are, and each centre conducts tests. I do not know how many tests per day. So, you are talking about lakhs and lakhs of tests, but as per your information you have filed only 418 complaints. Now, we would like to know whether there have been any prosecution, whether people have been arrested, whether they have been barred from practice and what further steps do you want to take to stop this because this is a very serious aspect. This Act is one thing, but there are other aspects also, which we need to look into.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक पी॰एन॰डी॰टी॰ एक्ट का सवाल है बाक़ायदा एक सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है जो इसको मानीटर करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम लोग कहते हैं कि वे मानीटर करें। लेकिन जो बात उन्होंने इस सवाल के साथ जोड़ी है कि केवल पीएनडीटी एक्ट नहीं अदर आसपैक्ट हैं। आप भी यह जानते हैं कि केवल कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत ज्यादा झकझोरने वाले जन-अभियान की जरूरत है। इसलिए हम केवल पीएनडीटी एक्ट पर गौर नहीं दे रहे हैं। पीएनडीटी अपने आप में एक चीज है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरीज देख रही हैं, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड देख रहा है, उसमें कितनी कम्पलेंट्स हैं शायद यह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को एक चीज बताना चाहती हूं कि मैंने जन-स्वास्थ्य के मुद्दों पर कैम्पेन मूड अपनाया है, एक अभियान का रूप अपनाया है, उसमें "सेव द गर्ल चाइल्ड" एक है और बहुत बड़े कैम्पेन के रूप में यह चला और आपसे ही मैंने वह कैम्पेन लांच करवाया था। आपने देखा होगा कि इस बार हमने बाक़ायदा एक ब्रांड एम्बेसडर उसके लिए नियुक्त की है। एक नेशनल कमिटमेंट कैम्पेन हमने चलाया है। अभी 26 जनवरी के लिए एक टैब्ल्यु हम लोगों ने चलाया है। हम ऐसी सेलेब्रिटीज जिनके यहां केवल बेटियां हैं, उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके चला रहे हैं, बिल्कुल आत्मा को झकझोरने वाले नारे, आम लोगों को यह प्रेरणा देने वाली चीजें हैं कि बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ ह्यूमर देते हुए चीजें चला रहे हैं। जैसे मैंने कहा था लड़कों को कि कुंवारे रह जाओगे अगर लड़कियों का रेशो इतना कम हो जायेगा। पृथ्वीराज जी, एक अभियान के तौर पर

सरकार ने इसको लिया है और मुझे लगता है कि उसका पीएनडीटी एक्ट पर भी असर होगा क्योंकि इस अभियान का असर जब आम जनता पर होगा तो वे आबार्शन कराने के लिए कम जायेंगे और जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उसमें भी कमी आयेगी। केवल एक्ट बनाकर चुप रहने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उस एक्ट की आवश्यकता न पड़े, उस एक्ट के अगेंस्ट आफेंस रजिस्टर्ड ही न करने पड़ें। लोग ऐसे अपराध करें ही नहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने प्रारम्भ किया है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है।

श्री सभापति: अब आप गोयनका जी को प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर, मैंने अन-रजिस्टर्ड यूजर्स के बारे में सवाल पूछा था। कितनी अल्ट्रासाउंड मशीन इंडिया में बनती हैं या इम्पोर्ट होती हैं इसकी जानकारी आपके पास है। अगर 21 हजार रजिस्टर्ड यूनिट हैं तो कितने अन-रजिस्टर्ड प्रैक्टिसनर्स हैं क्या इसकी जानकारी आपके पास है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, अगर अन-रजिस्टर्ड का नम्बर हमारे पास होता तो हम उनको रजिस्टर्ड ही न करवा देते। इसलिए हमारे पास रजिस्टर्ड की ही जानकारी है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: सर, ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: छोड़िये। अगर अन-रजिस्टर्ड की जानकारी होती तो एक्शन ही हो जाता।

श्री आर० पी० गोयनका: सभापति महोदय, मंत्री जी ने ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: अब आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? छोड़िये। यह बुढ़ापे वालों का प्रश्न नहीं है। चलिए, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री आर० पी० गोयनका: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया है, पूरा दिया है। मेरा एक सुझाव है कि जिन पांच स्टेट्स में लड़कियों की दर अभी भी कम है, उनमें अगर मुख्य मंत्री लड़कियां बन जाएं तो उसका बहुत अच्छा असर होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, ऐसी स्टेट्स जहां पर पापुलेशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और सेव दी गर्ल चाइल्ड की भी, उनमें से दो राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिला मुख्य मंत्री बन गयी हैं। (व्यवधान)

*Q. [The questioner (Shri S. Agniraj) was absent. for answer *vide* page 15 infra.]